करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

सितंबर 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **5**

➢ आठ नए सरकारी कॉलेजों की घोषणा 5

➢ उत्तराखंड के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा 5

➢ हिमालय दिवस के अवसर पर वेबिनार आयोजित 5

➢ ऋषिकेश एम्स में खुला प्रदेश का पहला पीएनबी डिजिटल बैंक 6

➢ रोपवे निर्माण के लिये MoRTH के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड 6

➢ नैनीताल में 119वाँ नंदा देवी महोत्सव शुरू 7

➢ उत्तराखंड में एलएसडी वायरस का पहला केस 7

➢ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 8

➢ राज्य के पहले ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन 8

नोट :

- नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का समापन 8
- सहकारी बैंकों की एटीएम वैन 9
- वाहनों का फ्लैग ऑफ 9
- भारत-नेपाल संयुक्त अभ्यास 9
- काष्ठ कला प्रशिक्षण में हैंड होल्डिंग सपोर्ट कार्यक्रम 10
- उत्तराखंड ने आयुष्मान भारत योजना, आयु कार्डों पर शुल्क में छूट दी 10
- देहरादून में बनेगा नेत्र संग्रह केंद्र 11
- टिहरी बांध 11
- पर्यटकों के लिये लग्जरी वैन 'कारवां' का उद्घाटन 12
- अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव 12
- कोविड-19 प्रभावित परिवहन व्यवसायियों के लिये आर्थिक सहायता योजना 12
- मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना की घोषणा 13

नोट :

- ‘ज़िम्मेदार पर्यटन’ पर कार्यशाला 13
- दून में ‘उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट’ शुरू 13
- उत्तराखंड में खुलेंगी तीन नई खाद्य जाँच प्रयोगशालाएँ 14
- देश का पहला प्राकृतिक रूप से विकसित फर्नाटम (संरक्षण क्षेत्र) 14
- ‘निर्भया: एक पहल’ 15
- पुलिस यातना 15

नोट :

उत्तराखंड

आठ नए सरकारी कॉलेजों की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 4 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आठ नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की। साथ ही कहा कि सात डिग्री कॉलेजों को पीजी कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएँ शासकीय स्नातकोत्तर (पीजी) कॉलेज, रायपुर मालदेवता में विज्ञान खंड के उद्घाटन के अवसर पर की।
- उन्होंने कहा कि देहरादून शहर, हरिद्वार शहर (भूपतवाला), हल्द्वानी शहर, गदरपुर ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा में दन्यां, पौड़ी में कल्जीखाल और खिर्सू तथा चमोली में देवल में नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे।
- वहीं मुनस्यारी (पिथौरागढ़), गैरसैंण (चमोली), कपकोट (बागेश्वर), सोमेश्वर, हल्दुचौड़ (नैनीताल), लक्सर (हरिद्वार) और थलीसैण (पौड़ी) के सरकारी कॉलेजों को पीजी कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा।
- इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल तथा आधुनिक लेक्चर हॉल का निर्माण किये जाने की भी घोषणा की।

उत्तराखंड के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा

चर्चा में क्यों ?

- 8 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने कार्यकाल से 2 वर्ष पहले पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पिछले महीने 28 अगस्त को राज्य के राज्यपाल के रूप में अपने तीन वर्ष पूरे किये थे, उनके कार्यकाल में अभी भी दो साल बाकी थे।
- 64 साल की बेबी रानी मौर्य ने अपने पूर्ववर्ती कृष्ण कांत पॉल के पाँच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगस्त 2018 में उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी।
- वे पूर्व में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी हैं। 1995 से 2000 तक वे उत्तर प्रदेश में आगरा की मेयर रहीं, जबकि 2001 में वे राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य और 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रहीं।
- दलित नेता बेबी रानी मौर्य ने 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एतमादपुर सीट से विजय प्राप्त की थी।

हिमालय दिवस के अवसर पर वेबिनार आयोजित

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस वेबिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निजी इलेक्ट्रिक दो पहिया व चार पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, जोकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ये प्रोत्साहन राशि निजी प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम 5000 दोपहिया वाहनों को वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा 7500 रुपए, जो भी कम हो तथा 1 हज़ार चार पाहिया वाहनों के लिये वाहन के मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50000 रुपए, जो भी कम हो देय होगी।
- प्रोत्साहन की धनराशि बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक व वित्तीय संस्थाओं या डीलर को उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिये स्थापित किये जाने वाले चार्जिंग स्टेशन हेतु समस्त व्यक्ति/संस्था अनुमन्य होंगे, जिनके पास पर्याप्त स्थान होने के साथ स्थानीय नगर निकाय की अनुमति प्राप्त हो।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद् स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में 'सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार' प्रारंभ करने की घोषणा की।
- वेबिनार में हिमालय यूनाटेड मिशन (हम) की पुस्तक 'हिमालय दिवस' को भी विमोचित किया गया।

ऋषिकेश एम्स में खुला प्रदेश का पहला पीएनबी डिजिटल बैंक

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रविकांत और पीएनबी देहरादून के अंचल प्रबंधक आरडी सेवक ने प्रदेश के पहले पीएनबी डिजिटल बैंक (ईज़ आउटलेट) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- बिना कर्मचारी के संचालित होने वाले डिजिटल बैंक में सभी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। डिजिटल बैंक राजकीय और साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी 24 घंटे काम करेगा।
- एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि संस्थान में स्थापित पीएनबी के डिजिटल बैंक का लाभ मरीज़ों, तीमारदारों के साथ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा।
- पीएनबी के अंचल प्रबंधक आरडी सेवक ने कहा कि पीएनबी का डिजिटल बैंक कोरोना काल के बीच एक बड़ी पहल है। अब लोग भीड़भाड़ से बचते हुए बैंकिंग सेवा का लाभ उठा पाएंगे।

रोपवे निर्माण के लिये MoRTH के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसके साथ ही रोपवे निर्माण के लिये सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अनुबंध करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव उत्तराखंड डॉ. एस.एस. संधु की मौजूदगी में उत्तराखंड पर्यटन की ओर से युगल किशोर पंत, अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एनएचएलएमएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गौड़ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन गंतव्यों तक अधिक-से-अधिक पर्यटकों व श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक पहुँचाना और पर्यटकों का गमनागमन वर्ष भर उपलब्ध कराना है।

नोट :

- उत्तराखंड में रोपवे निर्माण के लिये सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नोडल विभाग बनाया गया है।
- रोपवे निर्माण के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से डीपीआर तैयार कर काम शुरू किया जाएगा।
- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नियंत्रणाधीन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के केदारनाथ रोपवे, नैनीताल रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे, पंचकोटी से नई टिहरी, औली से गौरसू, मुनस्यारी से खलिया टॉप तथा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक सात रोपवे के डीपीआर गठन एवं निर्माण की कार्यवाही राज्य सरकार के साथ मिलकर की जाएगी।
- इससे पहले पर्यटन विभाग मसूरी, पूर्णागिरि और सुरकंडा देवी रोपवे को पीपीई मोड पर बनाने एवं संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की गई है। इसमें से सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन इस वर्ष के अंत में शुरू कर दिया जाएगा।

नैनीताल में 119वाँ नंदा देवी महोत्सव शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 11 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के नैनीताल में श्री राम सेवक सभा के सभागार में विधि-विधान से 119वें सातदिवसीय नंदा देवी महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्य अतिथि नीलेश आनंद भरणे (पुलिस उप-महानिरीक्षक, कुमाऊँ क्षेत्र) ने कहा कि नंदा देवी महोत्सव नैनीताल की विशेष पहचान का हिस्सा है। युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ-साथ देशी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिये इस तरह के त्योहारों का आयोजन बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गए। लोक नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों ने स्थानीय लोगों एवं भक्तों के उत्साह को और बढ़ा दिया।
- इस अवसर पर पर्यावरणविद् यशपाल रावत द्वारा प्रस्तुत इक्कीस पौधे, जो सरियाताल में कटे हुए पौधे की क्षतिपूर्ति के लिये लगाए जाएंगे, की भी पूजा की गई।
- संयुक्त दंडाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि 14 सितंबर (अष्टमी) को देवी-देवताओं की मूर्तियों को भक्तों के दर्शन के लिये रखा जाएगा और एक बार में 30 भक्तों को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी।

उत्तराखंड में एलएसडी वायरस का पहला केस

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2021 को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा दी गई रिपोर्ट में उत्तराखंड के काशीपुर ब्लॉक की चार गायें एलएसडी (लंपीस्किन डिजीज) वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इससे पहले एलएसडी बीमारी के मामले वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में देखने को मिले थे।
- एलएसडी पशुओं की एक विषाणुजनित बीमारी है, जिसके संक्रमण से पशुओं के शरीर में जगह-जगह गाँठें बन जाती हैं। इसका वायरस पशुओं में मक्खी, मच्छर, पशु से पशु के संपर्क एवं पशु लार आदि से पैलता है।
- इस बीमारी में पशु मृत्यु दर कम होती है, किंतु पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में गिरावट आ जाती है।
- पशुपालन विभाग के अनुसार, लंपीस्किन वायरस 1929 में पहली बार जिम्बावे के दुधारु पशुओं में पाया गया था।

लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह

चर्चा में क्यों?

- 15 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के राजभवन में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- गुरमीत सिंह उत्तराखंड के आठवें राज्यपाल बने हैं।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर, 2021 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था।
- उत्तराखंड के पहले सिख राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, जिनके बाद गुरमीत सिंह दूसरे सिख राज्यपाल हैं।
- लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल भी हैं।
- लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का पैतृक गाँव जालाल (अमृतसर) में है।

राज्य के पहले ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- 16 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने नैनीताल में उच्च न्यायालय परिसर में राज्य के पहले ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बताया कि लोग अब ई-कोर्ट कार्यक्रम के तहत डिजिटल रूप से उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं। वादियों और प्रतिवादियों को मामलों की अद्यतन स्थिति, न्यायाधीशों के अवकाश और सुनवाई की तारीखों की भी जानकारी होगी।
- इसके अलावा, अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी ई-सेवा केंद्र में भी उपलब्ध होगी। लोग केंद्र के माध्यम से ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority- DLSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority- SLSA) और सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति से भी मुफ्त कानूनी सेवाएँ लेने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- उन्होंने कहा कि यह राज्य का पहला ई-सेवा केंद्र है और अगला केंद्र अल्मोड़ा में खोला जाएगा। वर्तमान समय में ऐसे केंद्रों के महत्त्व को देखते हुए भविष्य में सभी ज़िला न्यायालयों में ऐसे सेवा केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का समापन

चर्चा में क्यों?

- 17 सितंबर, 2021 को देवी नंदा और सुनंदा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ 119वें नंदा देवी महोत्सव का समापन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस महोत्सव का आयोजन श्री राम सेवक सभा और नैनीताल ज़िला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- इस महोत्सव में काफी संख्या में भक्तों ने नैना देवी मंदिर में देवी-देवताओं को नमन किया। महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की गईं।
- उत्सव के अंतिम दिन अल्मोड़ा के एक सांस्कृतिक दल ने नैना देवी मंदिर के बाहर प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों की प्रस्तुति सहित अन्य प्रदर्शनों का भी टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण किया गया।

नोट :

- देवी-देवताओं को शहर भर में एक औपचारिक जुलूस में निकाला गया, जिसके बाद मूर्तियों को झील में विसर्जित किया गया।
- महोत्सव के अंतिम दिन अंजुमन-ए-बाल्टिस्तानी शिया समुदाय के सदस्यों ने देवी की पूजा करने आने वाले भक्तों को जल पिलाया।

सहकारी बैंकों की एटीएम वैन

चर्चा में क्यों?

- 17 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर सहकारी बैंकों की मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन राज्य के विभिन्न ज़िलों में नकद निकासी की सुविधा प्रदान करने के साथ ही राज्य में आने वाले पर्यटकों की भी मदद करेंगी।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर पाँच एटीएम मोबाइल वैन को मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जबकि शेष पाँच को ज़िला सहकारी बैंक मुख्यालय से उनके गंतव्य के लिये रवाना किया गया।
- सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी बैंकों की मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से हर ज़िले में उपलब्ध कराई जा रही है।
- उन्होंने कहा कि इन एटीएम मोबाइल से कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक खाते से नकदी निकाल सकता है।
- उल्लेखनीय है कि मोबाइल एटीएम वैन ने महामारी के दौरान राज्य के लोगों की मदद में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।

वाहनों का फ्लैग ऑफ

चर्चा में क्यों?

- 20 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एटीएमयुक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया।

प्रमुख बिंदु

- इन वाहनों का उपयोग राज्य की जनता को वित्तीय साक्षर बनाने एवं एटीएम के माध्यम से कर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में किया जाएगा।
- ग्रामीण बैंक मोबाइल एटीएम वैन द्वारा राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को एटीएम के माध्यम से लेने-देने के साथ वित्तीय साक्षरता हेतु जागरूकता भी प्रदान की जाएगी।
- इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के नवम् वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया।
- उपर्युक्त सभी प्रयास वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल इंडिया मिशन को अधिक सशक्त बनाने में कारगर साबित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि नाबार्ड के सहयोग से पूर्व में प्रदत्त एक वित्तीय साक्षरता वाहन का उपयोग अल्मोड़ा जनपद में किया जा रहा है।

भारत-नेपाल संयुक्त अभ्यास

चर्चा में क्यों?

- 20 सितंबर, 2021 को 15वाँ भारत-नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'सूर्य किरण' पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। इस अभ्यास का समापन 3 अक्तूबर को होगा।

प्रमुख बिंदु

- इससे पहले शनिवार को नेपाली सेना की टुकड़ी पिथौरागढ़ पहुँची, जिसका पारंपरिक सैन्य स्वागत किया गया।

- उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC), लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. महल ने सभा को संबोधित किया और टुकड़ियों को आपसी विश्वास, अंतर-संचालन को प्रशिक्षित तथा मज़बूत करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये प्रोत्साहित किया।
- इस आयोजन में दोनों सेनाओं के लगभग 650 रक्षाकर्मी भाग ले रहे हैं। अभ्यास में भारतीय सेना और नेपाली सेना की एक-एक इन्फैंट्री बटालियन अंतर-संचालन विकसित करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों एवं आपदा राहत कार्यों के अपने अनुभव को साझा करने के लिये एक साथ प्रशिक्षण लेंगे।

काष्ठ कला प्रशिक्षण में हैंड होल्डिंग सपोर्ट कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- 21 सितंबर, 2021 को गढ़वाल ज़िलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने जनपद पौड़ी गढ़वाल में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत काष्ठ कला प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हैंड होल्डिंग सपोर्ट कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर ज़िलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य व अन्य गणमान्य द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं किट वितरण किया गया। साथ ही, ज़िलाधिकारी ने हस्तशिल्प द्वारा बनाए गए, मंदिरों के शिल्प व मॉडल का अवलोकन कर उनके कार्य के बारे में जानकारी ली।
- उत्तराखंड हथकरघा परिषद के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा प्रशिक्षण को पूर्ण कर हस्तशिल्प कला की बारीकियों को सीखा।
- ज़िलाधिकारी डॉ. जोगदंडे ने कहा कि जनपद में पहली बार हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी हो रही है, जो कि इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
- उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनपद के प्राचीन धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों को भी काष्ठ कला से बनाकर प्रचारित-प्रसारित करने तथा जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले गणमान्य अतिथियों को गुलदस्तों के स्थान पर हस्तशिल्प से बने उत्पाद प्रतीकचिह्न के रूप में देने का निर्देश दिया।

उत्तराखंड ने आयुष्मान भारत योजना, आयु कार्डों पर शुल्क में छूट दी

चर्चा में क्यों?

- 23 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना- ABY) की तीसरी वर्षगाँठ पर राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये शुल्क में छूट देने की घोषणा की। अभी तक कार्ड बनाने के लिये 30 रुपए शुल्क लगता था।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत योजना' के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'आरोग्य मंथन-3.0' में यह घोषणा की।
- उन्होंने योजना के तहत अस्पतालों के दावों के निपटारे के लिये सात दिनों की समय-सीमा भी तय की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (AAUY) के तहत कवर किया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत अब तक कुल 3.5 लाख लोगों का इलाज हो चुका है और इस पर 460 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।
- स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि योजना के तहत कुल 102 सरकारी और 113 निजी अस्पताल पैनल में शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि पैनल में शामिल प्रत्येक अस्पताल में योजना के संबंध में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएँ।

- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिससे सभी निजी अस्पतालों का इन योजनाओं के पैनल में होना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छूटे हुए परिवारों को योजना के तहत लाने के लिये प्रखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।

देहरादून में बनेगा नेत्र संग्रह केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल (GCEH), देहरादून को नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत नेत्र संग्रह केंद्र शुरू करने की अनुमति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक (DG) डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने अस्पताल के अधिकारियों को इस साल 1 नवंबर से पहले केंद्र शुरू करने का निर्देश दिया है।
- इसके शुरू होते ही GCEH यह सुविधा देने वाला राज्य का पहला केंद्र होगा।
- राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ. सरोज नैथानी ने कहा कि केंद्र के लिये GCEH में आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का विकास किया जाएगा। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर गढ़वाल संभाग में रहने वाले लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण का लाभ मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि GCEH केवल नेत्र संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करेगा और एकत्रित नेत्रगोलक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), ऋषिकेश या हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट, देहरादून के नेत्र बैंकों में रखा जाएगा।

टिहरी बांध

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2021 को टिहरी बांध जलाशय को पहली बार 830 मीटर ऊँचाई तक भरा गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि टिहरी जलविद्युत परियोजना के तहत अभी तक इसे 828 मीटर तक ही भरा जाता है, किंतु अगस्त महीने में ही सरकार से अनुमति मिलने के बाद जल के स्तर में वृद्धि की गई। इससे टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर पाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिकीविदों द्वारा हिमालयी क्षेत्र में बाँधों के निर्माण से आपदाओं की संभाव्यता को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। ऐसे में हिमालयीय पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता को देखते हुए बाँधों के जलस्तर में वृद्धि गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है, जैसे हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से तपोवन-विष्णुगढ़ परियोजना के क्षेत्र में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
- भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बाँध एवं जल विद्युत परियोजना का संचालन टिहरी हाइड्रो पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
- इस परियोजना द्वारा वर्ष 2006 से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। टिहरी जलविद्युत परिसर (2400 मेगावाट) के तीन घटक हैं-
  - टिहरी बांध एवं जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)
  - कोटेश्वर बांध एवं जलविद्युत परियोजना (400 मेगावाट)
  - टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (1000 मेगावाट)

नोट :

पर्यटकों के लिये लग्ज़री वैन 'कारवां' का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- 24 सितंबर, 2021 को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों की यात्रा हेतु उत्तराखंड के लोगों एवं पर्यटकों के लिये उच्च आराम सुविधाओं से लैस विशेष वैन 'कारवां' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह कैंपिंग वाहन यात्रा के शौकीन पर्यटकों के लिये घर जैसी सभी सुविधाएँ मुहैया कराएगा। इस वाहन में एलसीडी टीवी, सैटेलाइट टीवी, जीपीआरएस नेविगेशन सिस्टम, वाशरूम, पेंट्री, माइक्रोवेव और अन्य सुविधाएँ हैं।
- इस वाहन से कोई भी सड़क मार्ग से कहीं भी यात्रा कर सकता है। इसका सीधा लाभ पर्यटकों और उत्तराखंड के लोगों, दोनों को होगा।
- उन्होंने कहा कि इस कारवां को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोज़गार योजना में शामिल किया गया है, साथ ही इसे पर्यटन योजना वर्ष 2018 के तहत एमएसएमई के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, जिसमें स्थानीय लोग 'कारवां' खरीद सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव

चर्चा में क्यों?

- 24 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य में पहली बार आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- देहरादून में इस अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन 24 से 26 सितंबर तक किया जाएगा।
- महोत्सव में हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों से सेब उत्पादकों ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव में देश भर से तकरीबन 50 सेब की वैरायटी सम्मिलित की गईं।
- महोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्तराखंड के सेब की पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँचाना है ताकि उत्तराखंड की सेब की ब्रॉन्डिंग राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हो सके।
- इस अवसर पर धामी ने बागवानी श्रमिकों को कोविड योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की, साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन सेब के लिये बजट दोगुना करने की भी घोषणा की।

कोविड-19 प्रभावित परिवहन व्यवसायियों के लिये आर्थिक सहायता योजना

चर्चा में क्यों?

- 26 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों (चालक/परिचालक/क्लीनर) को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना का विधिवत् शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश के 103235 चालक/परिचालक/क्लीनर को 2000 रुपए प्रतिमाह की राशि 6 माह तक प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के प्रथम चरण में 36,100 परिवहन व्यवसायियों को डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 34,635 चालक, 930 परिचालक तथा 535 क्लीनर शामिल हैं।
- इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा परिवहन व्यवसायी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना' प्रारंभ करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोज़गार के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएँ आर्थिक स्वावलंबी बनेंगी।
- इस योजना के तहत महिलाओं को दिये गए ऋण में 30 प्रतिशत अथवा 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ अविवाहित, तलाकशुदा, विकलांग आदि महिलाएँ प्राप्त कर सकेंगी।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी क्षेत्रों में महाप्रबंधक, ज़िला उद्योग केंद्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।

'ज़िम्मेदार पर्यटन' पर कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2021 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (USAC) ने हिमालयन नॉलेज नेटवर्क (HKN) के साथ 'ज़िम्मेदार पर्यटन' पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यशाला में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और गढ़वाल एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालयों के साथ-साथ पर्यटन और वन जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
- कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए यूएसएसी के निदेशक एम.पी.एस. बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की बहुत संभावनाएँ हैं। राज्य भर में ज़िम्मेदार पर्यटन लाने की आवश्यकता है। इस तरह की पहल से स्थानीय लोगों के लिये भी रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- एचकेएन के नोडल अधिकारी गजेंद्र सिंह ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में 145 से अधिक विश्वविद्यालय, 2,000 प्रोफेसर और 500 वैज्ञानिक अनुसंधान में शामिल हैं। अधिकांश संगठनों में सूचना साझा करना काफी सीमित है और इस मामले से निपटने के लिये एचकेएन की स्थापना की गई है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (USAC) अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के लिये उत्तराखंड राज्य में नोडल एजेंसी है तथा राज्य और उसके लोगों के लाभ के लिये अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी को नियोजित करने का अधिकार रखता है। इसका गठन 2005 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था।

दून में 'उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट' शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 26-27 सितंबर, 2021 को देवभूमि उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोदिवसीय 'उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 26 सितंबर को वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने इस फेस्ट का उद्घाटन करते हुए उत्तराखंड में पर्वतारोहण संबंधी सेवाओं के लिये 'सिंगल विंडो सिस्टम' का शुभारंभ किया।

नोट :

- इस एडवेंचर फेस्ट का आयोजन फिक्की एफएलओ के सहयोग से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) द्वारा किया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाएँ कीं। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योगों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर विशेष रूप से उद्योग विभाग की जगह पर्यटन विभाग द्वारा ही कार्यवाही की जाएगी।
- शहरी विकास विभाग और आवास विभाग द्वारा विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के लिये बहुस्तरीय कार-लिफ्ट स्थान स्थापित करने हेतु परियोजना शुरू की जाएगी।
- उन्होंने उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को एक स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल उद्योग के रूप में विकसित करने के मार्ग तलाशने के लिये राज्य में पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ व पर्यटन मंत्रालय के तहत एक समर्पित ईको टूरिज्म विंग का गठन करने की घोषणा की।
- इसके साथ ही उन्होंने पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान को पर्यटन विभाग को सौंपने की घोषणा की। अभी नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान को खेल विभाग संचालित करता है।
- वन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रोमांच से भरपूर 'साहसिक पर्यटन' की असीम संभावनाएँ हैं, जो भारत और विश्वस्तर पर पर्यटकों के बीच अपार उत्साह पैदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसी साल नवंबर में कुमाऊँ के रामनगर में साहसिक कार्य पर निवेश सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा।
- लॉन्च किये गए 'सिंगल-विंडो पोर्टल' के बारे में उन्होंने कहा कि यह पोर्टल राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिये सुगमता सुनिश्चित करेगा।
- इस फेस्ट में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बलून, कैंपनिंग, आईसकिंग, कयाकिंग समेत स्थानीय व्यंजन के विभिन्न स्टॉल और कार्यशालाएँ शामिल थे, जो आकर्षण का केंद्र रहे।

उत्तराखंड में खुलेंगी तीन नई खाद्य जाँच प्रयोगशालाएँ

चर्चा में क्यों?

- 28 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने उत्तराखंड में तीन नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ खोलने के आदेश दिये। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र में एक-एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- ये प्रयोगशालाएं देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में स्थापित की जाएंगी।
- वर्तमान में प्रदेश में एक ही खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, जो रुद्रपुर में स्थित है।
- मुख्य सचिव ने राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये पोर्टल आधारित निगरानी शुरू करने, नियमित रूप से अभियान चलाने और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
- उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिये छोटी-छोटी वीडियो क्लिप बनाई जानी चाहिये। साथ ही उन्होंने होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्वच्छता रेटिंग अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया।

देश का पहला प्राकृतिक रूप से विकसित फर्नाटम (संरक्षण क्षेत्र)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देश का पहला प्राकृतिक रूप से विकसित फर्नाटम (संरक्षण क्षेत्र) अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत में कालिका वन रेंज में तैयार हो चुका है। विभाग द्वारा इसे एशियाई स्तर का अध्ययन स्थल बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि शोधकर्त्ताओं को जुरासिक युग की इन फर्न प्रजातियों के बारे में पता चल सके।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) संजीव चतुर्वेदी द्वारा हाल ही में कालिका वन अनुसंधान केंद्र के दलमोती रोड पर नया फर्नाटम खोला गया था।

नोट :

- उन्होंने बताया कि फर्न प्रजातियाँ औषधीय रूप से बहुत फायदेमंद हैं और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। इनके संरक्षण के लिये कालिका में एक हेक्टेयर क्षेत्र में फर्नाटम तैयार किया गया है।
- संजीव चतुर्वेदी के अनुसार, फर्नाटम में उत्तराखंड के उच्च, मध्य और निचले हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों का भंडार है और जल्द ही इस फर्नाटम को एशिया मंत अपनी तरह का सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप से विकसित क्षेत्र बनाया जाएगा।
- वर्तमान में 103 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं। इनमें से 95 फीसदी प्रजातियाँ उत्तराखंड से हैं।
- फर्नाटम में पाई जाने वाली कई फर्न प्रजातियों में से, हंसराज उत्तराखंड की एक विशिष्ट फर्न प्रजाति है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है और इसकी जड़ों का उपयोग सर्पदंश के प्रभावों का मुकाबला करने के लिये किया जाता है। कालिका में इसकी 10 प्रजातियाँ हैं।
- चतुर्वेदी ने बताया कि केरल में हरे और शेड घरों में फर्न प्रजातियों के लिये एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, लेकिन कालिका में स्थानीय जलवायु के अनुसार प्राकृतिक रूप से देश का पहला फर्नाटम तैयार किया गया है। इसे फर्न प्रजातियों के अध्ययन का नोडल केंद्र बनाया जाएगा।

'निर्भया: एक पहल'

चर्चा में क्यों ?

- 29 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करने के लिये 'निर्भया: एक पहल' लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वाभिमान एवं स्वावलंबन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन 'शक्ति' प्रारंभ किया गया था। इस मिशन के तीसरे चरण में अब 'निर्भया: एक पहल' अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसका वित्तीयन निर्भया फंड से किया जाएगा।
- इसके तहत राज्य के प्रत्येक ज़िले से लगभग 1000-1000 महिलाओं, अर्थात् कुल 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित की जाएगी।
- इस तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण अभियान का क्रियान्वयन राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें उन्हें यह बताया जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिल सकता है, जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं।
- उद्यम शुरू करने के लिये प्रशिक्षण के पश्चात् अगले तीन महीनों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूंजी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन नंबर 18002126844 तथा वेबसाइट https://msmemissionshakti.in / एवं एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ताकि महिला उद्यमियों को उद्यमिता संबंधी सभी सूचनाएँ एक ही जगह पर प्राप्त हो सकें।

पुलिस यातना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में गोरखपुर पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं से कानपुर निवासी कारोबारी की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने भारत में पुलिस द्वारा लोगों के विरुद्ध हिंसा के प्रयोग एवं हिरासत में मृत्यु जैसे विषयों को पुन: चर्चा का विषय बना दिया है।

प्रमुख बिंदु

- गैर-सरकारी संस्था 'कॉमन काज' की रिपोर्ट 'स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया' के अनुसार, प्रत्येक 5 में से 3 पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अपराधियों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग उचित है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के विरुद्ध 2000 से 2018 के बीच 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किये गए हैं।

- पुलिस द्वारा हिंसा के लिये उत्तरदायी कारक-
  - भारत में यातना के विरुद्ध कानूनों की अनुपस्थिति।
  - पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही का न होना।
  - पुलिस सुधारों की धीमी गति।
  - दोषसिद्धि की निम्न दर।
- पुलिस यातना रोकने के लिये प्रावधान-
  - डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि यातनाओं के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद-21 में दिये गए जीवन के अधिकार के तहत एक मूल अधिकार है।
  - दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 41A, 41B, 41C, 41D में गिरफ्तारी एवं निरोध (Detention) के लिये तार्किक आधार एवं नियम बताए गए हैं।
  - भारतीय दंड संहिता की धाराएँ- 330, 331, 348
  - भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा- 25 और 26
- उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा 'यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' पर हस्ताक्षर करने के बावजूद उसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है।

दृष्टि The Vision